कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एफ-4 / 13 / 2022 / 10-11 / 2 13.5 प्रेषक. भोपाल, दिनांक25-05-23

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश।

प्रति,

उप वन महानिदेशक, (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई—5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:— ग्वालियर जिले के अंतर्गत वनमण्डल ग्वालियर 220 के.व्ही. उपकेन्द्र रामिसया सरकार झांसी रोड़ ग्वालियर से नवीन 1000 बिस्तर सरकारी अस्पताल में पावर सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.00 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना यंत्री, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6—एमपीबी 024/2022—बीएचओ/ दिनांक 03.03.2023

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 6—एमपीबी 024/2022—बीएचओ/ दिनांक 03.03.2023 से अधिरोपित शर्तों के तहत सैद्धान्तिक सहमित प्रदान करते हुए लेख किया गया है कि सैद्धान्तिक सहमित में समस्त अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जावेगा।

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन परियोजना यंत्री, पी. आई.यू. लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर ने अपने पत्र क्रमांक / 851 / तशा. / पी आई यू / ग्वा., दिनांक 17.05.2023 के अनुसार जानकारी निम्नानुसार है:—

A: Condition which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

शर्त	अधिरोपित शर्ते	शर्तों का पालन प्रतिवेदन
क्र.		_
1	The cost of compensatory afforestation on the CA land (6.00 ha. DFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled	
	for subsequent years.	

3.a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.00 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009, 5-3/2011-FC (Vol-II) dated 06/01/2022 The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the State Forest Department. The User Agency will defray the cost of such plantation.	शर्त के पालन में आवेदक से नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रू. 28,73,340 / — दिनांक 14.03.2023 ई—पोर्टल के माध्यम से एड—हॉक कैम्पा मद में जमा कराई गई है। आवेदक द्वारा औषधीय वृक्षारोपण की राशि रू. 21,37,729 / — ई—पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14.03.2023 को एड—हॉक कैम्पा मद में जमा कराई गई है। आवेदक द्वारा औषधीय वृक्षारोपण की राशि रू. 21,37,729 / — ई—पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14.03.2023 को एड—हॉक कैम्पा कराई गई है।
c)	Cost of the same shall be transferred to CAMPA fund via online / e.portal.	मद में जमा कराई गई है। सभी राशियां परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवाई गई है। जमा की गई राशि का विवरण निर्धारित प्रपन्न में संलग्न है।
4.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रू. 45,84,288 / —, नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रू. 28,73,340 / — एवं औषधीय वृक्षारोपण की राशि रू. 21,37,729 / — ई—पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14.03.2023 को एड—हॉक कैम्पा मद में जमा कराई गई है।
5.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	कार्यवाही की जा रही है।
6.	NOC from concerned departments (Road, Canal, Railway etc.) shall be submitted before Stage-II approval.	लेख किया है कि संबंधित विभागों की अपनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
7.	The Geo corrdinates fo towers constructed in forest area shall be provided before Stage-II approval.	संस्था सहमत है।
8.	Towers so erected shall be fenced (chain link fencing) by the User Agency.	इस शर्त को मान्य करने हेतु आवेदक संस्था सहमत है। —3—

9.	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	उक्त शर्त के संबंध में ई—ग्रीनवॉच की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसका आई.डी. क्रमांक 51693 है, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।
10.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
11.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in/).	पालन प्रतिवेदन ई—पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
12.	In case the State Forest Department issues working permission, a copy of the same shall be submitted to this office.	शर्त मान्य है। पालन किया जायेगा।

B: Condition which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

1.	Legal status of the forest land shall remain	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था
	unchanged.	द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by	प्रस्ताव में आवेदक विभाग से प्राप्त
2.		
	the Forest Department over 6.00 ha. degraded	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि से
	forest land Compartment No. 34, Forest Range-	रोपण किया जायेगा।
	Gwalior, Tehsil & District-Gwalior at the cost of	XIII II A A A A A A A A A A A A A A A A
	the user agency. As far as possible, a mixture of	
	local native species shall be planted and	
	monoculture of any species, especially non-native	
	species should be avoided.	() ()
3.	Additional amount of the NPV of the diverted	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था
	forest land, if any, becoming due after finalization	द्वारा नेट प्रजेंट वैल्यू की अतिरिक्त
	of the same by the Hon'ble Supreme Court of	देय राशि अदा करने का वचन पत्र
	India on receipt of the report from the Expert	
	Committee, shall also be charged by the State	दिया गया है, जो संलग्न है।
	Government from the User Agency. The User	
	Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
4.	User Agency shall restrict the felling of trees to	सहमत। इस शर्त के पालन हेतु
	1251 numbers / minimum number in the diverted	आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया
	forest land and the trees shall be felled under the	गया है।
	strict supervision of the State Forest Department	ाया ह।
	or the cost of felling of trees shall be deposited by	
	the User Agency with the State Forest	
	Department and State Forest Department shall	
	undertake the requisite felling.	,
	·	

5	The User Agency shall comply with the	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा
5.	guideline for laying transmission lines through forest as per Chapter 10 of FCA, 1980 Handbook, 2019.	वचन पत्र दिया गया है।
6.	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of the transmission line	सहमत।
	at suitable intervals to avoid bird hits.	चन्त्र प्राप्त कर्न के मान्य केन अपनेत्रक
7.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Dy. Conservator of Forest.	सहमत। इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
8.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
9.	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
10.	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
11.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials fore execution of the project work.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
12.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
13.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
14.		वचन पत्र दिया गया है।
15.	The User Agency and the State Government shall ensure compliance provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order (s) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.	सहमत है।

16. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ-4 / 13 / 2022 / 10-11 / 2 / 3 ८ प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक 25/05/23

- मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- 3. परियोजना यंत्री, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:51693

Project Name: POWER SUPPLY TO 1000 BEDDED HOSPITAL, GWALIOR

Year : 2023

To Register a new FCA Project, please click here Register a New FCA Project

To Lock the Details of FCA Project. Please click here Lock FCA Projects
 Add CA Land / Site Details to the Project. Please click here to add the CA Site*Land Details to the Project.

				Status of the Payr	nent ma	de by User Age	ncies		
7	Help								
		nt Value;	ditional Compensatory Affo	prestation; PCA : Pena	Compens			: Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional	Charges for protected area
	Verified Verified Verified	: This icon shows that the d : This icon shows that the d : This icon shows that the p	emand has been verified b	y Nodal Officer.	e yet to b Challan General	ted : This ico	on shows	er. s that the challan has been generated. is that the payment has been made.	
		1 This icon shows that the p	· ·	d on or after 15th Jul	_				1.001
		Select Region : Select User Agency :	Bhopal	·	Select St	ate:	Mad	thya Pradesh 🗸	
		Payment Status : Bank Name :	Select Paid Unpaid A Select All	II	Mode of	Payment :	Se	lect All⊶ ✓	
		Transaction Date (From) :	FP/MP/TRANS/143391/20			ion Date (To) :			
					SEARCH	4			
netino						~	HALLETTON PHER DONLLA		Me
	Proposal Detail FP/MP/TRANS/14339 (/viewreport.aspx? pid=FP/MP/TRANS/1- POWER SUPPLY TO 1 BEDDED HOSPITAL, 1	.43391/2021) 1000	Date of IN- PRINCIPLE (in Rs.) 30 03 Mar 2023 CA: 4584; PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 2873; Total: 9595;	288/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Medicinal Plantation2137729/ :	Paid	Pund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan	Mar 23 ion Bank India FT/RTGS hallan) Mar 23 Mar		

SWACHH (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. डी.डी. नगर भिण्ड रोड् ग्वालियर (म.प्र.)

ई-मेल : piugwalior@gmail.com

कमांक/851 तरा . | ची आई सू आ .

दिनांक 17 65 2023

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

Forest Department.

विषय-ग्वालियर जिले के अन्तर्गत 220 के.व्ही. उपकेन्द्र रामसिया सरकार झांसी रोड, ग्वालियर से नवीन 1000 बिस्तर सरकारी अस्पताल में पावर सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.000 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना यंत्री पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग को उपयोग पर देने बावत।

(Proposal No.-FP/MP/TRANS/143391/2021)

संदर्भ-1-भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एम. पी.बी 024/2022-बी.एच.ओ. दिनांक 03.03.2023

2-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक/एफ-4/13 /2022 /10-11/995 दिनांक 06.03.2023

3-आपके कार्यालय का पत्र कमांक/मा.चि./23/1963 दिनांक 13.03.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के प्रकरण में अनुरोध है कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत 220 के. व्ही. उपकेन्द्र रामसिया सरकार झांसी रोड, ग्वालियर से नवीन 1000 बिस्तर सरकारी अस्पताल में पावर सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.000 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना यंत्री पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग को उपयोग पर देने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक / 6-एम.पी.बी 024 / 2022-बी.एच.ओ. दिनांक 03.03.2023 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मू-प्रबंध म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/एफ-4/13/2022/10-11/995 दिनांक 06.03.2023 के संलग्न प्राप्त भारत सरकार द्वारा शर्त कमांक (A) 01 से 12 तक एवं (B) 01 से 16 तक अधिरोपित शर्तों का आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त जारी स्वीकृति के अनुसार राशि जमा करने के उपरान्त शर्तवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

A. Conditions which need to be complied prior with handing over of forest land by the State

(6	7
8.	7	2
19	12)	5

المقا لناما أناما المقا

S. No.	Condition	Reply
1 98	The cost of compensatory afforestation on the CA land (6.00 ha DFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposted in advance with the State Forest Department by the scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	उक्त शर्त के पालन में क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि 4584288/— रूपये ई—पोर्टल के माध्यम से व्हाउचर नम्बर—140/4210 / 032022—23/0008 दिनांक 13. 03.2023 को से कैम्पा में जमा की गई है। जमा की गई राशि का विवरण परिशिष्ट—1 पर संलग्न है।
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.00 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 565 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated	उक्त शर्त के पालन में नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि 2873340/-रूपये ई-पोर्टल के माध्यम से व्हाउचर नम्बर-140/4210 / 032022-23/0008 दिनांक 13.

	18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006 FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009, 5-3/2011-FC (Vol-II) dated 06-01-2022.	03.2023 को से कैम्पा में जमा की गई है। जमा की गई राशि का विवरण परिशिष्ट—1 पर संलग्न है।
3 (a)	The user agency in consultation with the state Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line for execution of the said scheme to the state Forest Department.	उक्त शर्त के पालन में औषधीय रोपण की राशि 2137729/— रूपये ई—पोर्टल के माध्यम से व्हाउचर नम्बर—140/4210 / 032022—23/0008 दिनांक 13. 03.2023 को से कैम्पा में जमा की गई है। जमा की गई राशि का विवरण परिशिष्ट—1 पर संलग्न है।
b	The User Agency will defray the cost of such plantation.	शर्त मान्य है।
С	Cost of the same shall be transferred to CAMPA fund via online/e-portal.	शर्त मान्य है।
4	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	उक्त शर्त के पालन में समस्त राशियों को ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा जमा कराई गई है।
5	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	उक्त शर्त के पालन में एफ.आर. ए. प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है।
6	NOC from concerned departments (Road, Canal, Railway etc.) shall be provided before Stage-II approval.	उक्त शर्त के पालन में संबंधित विभाग का अनापितत प्रमाण पत्र प्राप्त कर शीघ्र प्रस्तुत किया जावेगा।
7	The Geo coordinates of towers constructed in forest area shall be provided before State-II approval.	शर्त मान्य है।
8	Towers so erected shall be fenced (Chain link, fencing) by the User Agency.	शर्त मान्य है।
9	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	5 含
11	The compliance report shall be uploaded on e-porta (https://parivesh.nic.in/).	। उक्त शर्त का शर्तवार पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर ऑन

		लाईन अपलोड किया जावेगा।
12	In case the State Forest Department issues working permission, a copy of the same shall be submitted to this office.	उक्त शर्त वनविभाग से संबंधित है।

B. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

S. No.	Condition	Reply वन भूमि का वैधानिक अपरिवर्तित रहेगा। शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था सहमत है।	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.		
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.00 ha. degraded forest land at Compartment No. 34, Forest Range-Gwalior, Tehsil & District-Gwalior at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	वन विभाग से संबंधित हैं।	
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त मान्य है।	
4	User Agency shall restrict the felling of trees to 1251 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the requisite felling.	शर्त मान्य है।	
5	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest as per Chapter 10 of FCA, 1980 Handbook, 2019.	शर्त मान्य है।	
6	The User Agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	शर्त मान्य है।	
7	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Conservator of Forest.		
8	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	। शर्त मान्य है।	

9	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त मान्य है।
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	शर्त मान्य है।
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	
12	The period of diversion under this approval shall be co- terminus with the period of the project life.	शर्त मान्य है।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त मान्य है।
14	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.	
15	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (S) and National Green Tribunal Order (S) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.	
16	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	

उपरोक्त समस्त अधिरोपित शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन मय प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति एवं कार्य करने की अनुमित देने का कष्ट करें।

संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निमाण विभाग ग्वालियर (म.प्र.)

प्रतिलिपि-

दिनांक

पृ० कमांक/
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल मध्यप्रदेश की ओर आपके पत्र
कमांक/एफ-4/13 /2022 /10-11/995 दिनांक 06.03.2023 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित है।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य के दौरान भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का आवेदक विभाग द्वारा पालन किया जावेगा। किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया जावेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग परियोजना यंत्री, (वि./यां.) पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग ग्वालियर वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं वनमण्डल कार्यालय द्वारा व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि की अतिरिक्त मांग की जाती है तो आवेदक विभाग उक्त जमा करने के लिये वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तित वन भूमि पर खड़े प्रभावित होने वाले 1251 वृक्षों अथवा कम से कम वृक्षों को वन विभाग की देख—रेख में काटा जावेगा। काटे गये वृक्षों की राशि जमा करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि वन क्षेत्र में ट्रांसिमशन लाईन वन संरक्षण अधिनियम, 1980, हैण्डबुक 2019 के अध्याय–10 के प्रावधान अनुसार डाली जावेगी। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि ट्रांसिमशन लाईन अपर कन्डेक्टर पर नियमित अन्तराल पर पक्षी विक्षेपक (डिफ्लेक्टर) लगाये जायेगें जिससे पिक्षयों को हानि न पहुंचे । उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग के परामर्श द्वारा व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि का आवेदक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर सीमांकित किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित भूमि के रेखाकंन (ले-आउट प्लान) में कोई बदलाव बिना भारत सरकार की अनुमित के नहीं किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य के दौरान वन क्षेत्र में मजदूरों को कोई कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य के दौरान मजदूरों को ईधन के रूप में एल. पी.जी. उपलब्ध कराई जावेगी। ताकि वन क्षेत्र एवं आसपास की वन सम्पदा को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण की जाने वाली सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन मार्ग का निर्माण नहीं किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक विभाग द्वारा भूमि लीज अवधि या परियोजना अवधि में से जो भी कम हो उसके लिये दी जावे। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगा। उक्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य विभाग को बिना भारत सरकार की अनुमित के नहीं दी जावेगी। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लेखित नियम, अधिनियम, दिशा निर्देश एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदि को मान्य किया जावेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है।